भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2511

दिनांक 10 दिसम्बर, 2024

पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि

2511. डॉ. थोल तिरूमावलवन :

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को लागू करने के लिए कोई योजना अथवा नीति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के सहयोग से कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषिरत महिला पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से समग्र भारत में 75 गांवों तक पहुंचने हेतु ''न्यूट्री-स्मार्ट गांव'' पर एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल हैं : कृषिरत महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, कुपोषण का मुकाबला करने हेतु स्थानीय रेसिपी के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का सदुपयोग करना एवं घरेलू कृषि एवं पोषण उद्यान के माध्यम से पोषण- संवेदी कृषि को लागू करना। किए गए सार्थक प्रयासों के परिणामस्वरूप कुल 171 जैव-प्रबलित किस्मों का विकास किया गया जिनमें 152 खेत फसल किस्में और 19 बागवानी फसल किस्में शामिल हैं। देश की पोषणिक सुरक्षा को हासिल करने में इन जैव प्रबलित किस्मों का विशेष महत्व है। इन किस्मों में अनिवार्य पोषक तत्वों यथा आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, लाइजिन, ट्रिप्टोफन, प्रो-विटामिन-ए, एंथोसायनिन, विटामिन-सी, ऑलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल के लिए सुधार किया गया है। कुछ किस्मों में अनेक पोषणिक-रोधी कारकों यथा इरूसिक अम्ल, ग्लूकोसिनोलेट्स तथा ट्रिप्सिन निरोधक की मात्रा में उल्लेखनीय कमी की गई है। सोयाबीन के दानों की स्वादहीनता में भी कमी लायी गयी है। पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा के साथ ये जैव-प्रबलित किस्में अधिक पैदावार देने वाली भी हैं, इसलिए ये किस्में देश की ''खाद्य एवं पोषण सुरक्षा'' को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं।

जैव-प्रबलित किस्मों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जाता है। इसे दलहन, चावल, गेहूं, मोटे अनाज (मक्का एवं जौ) तथा न्यूट्री अनाज (श्री अन्न) का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी लागू किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स (आईवाईएम) के रूप में मनाया गया। श्री अन्न में उच्च पोषण मान होते हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण साक्षरता पर जानकारी सृजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पोषण संवेदी कृषि संसाधन एवं नवाचार (एनएआरआई) कार्यक्रम भी लागू किया है। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा एनएआरआई कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण से भरपूर जैव-प्रबलित किस्मों के ऑन-फार्म परीक्षण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किए गए और प्रशिक्षण एवं विभिन्न प्रसार संबंधी गतिविधियां चलाई गईं। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पोषण उद्यान, पोषण थाली, मूल्य-संवर्धन, जैव-प्रबलित फसलों को प्रोत्साहन आदि के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रसार गतिविधियां आयोजित की गईं।

''विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहयोग'' स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रदान किया गया ताकि किसानों के बीच पोषण संवेदी कृषि सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न विषयी क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और बेहतर कृषि रीतियों को उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन, ज्ञानवर्धन दौरे, किसान मेला, किसान हित समूह की गतिशीलता का आयोजन किया गया, महिला खाद्य एवं पोषण समूह और पुरस्कृत किसानों के क्षेत्र में फार्म स्कूल की स्थापना की गई।

(ग) एवं (घ) : राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद ने वर्ष 2019-20 में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के साथ कार्य किया ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अधिकारियों के दो स्तरों यथा मध्य-वरिष्ठ अधिकारियों एवं फील्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा सकें। मॉड्यूल के दो सेट विकसित किए गए और उसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया। इसके उपरांत, परियोजना के वितरण के हिस्से के रूप में, मैनेज ने वर्ष 2021 से पोषण संवेदी कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संस्थागत रूप दिया है।

अभी तक राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा पोषण संवेदी कृषि पर कुल 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम (18 राष्ट्रीय स्तरीय एवं 2 अंतरराष्ट्रीय स्तरीय) आयोजित किए गए हैं जिनमें कुल 924 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

****